भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2810
उत्तर देने की तारीख 05 अगस्त, 2026

कर्नाटक में प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) योजना का कार्यान्वयन

2810. श्री एम. मल्लेश बाबूः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान कर्नाटक में विशेषकर कोलार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित पीएम-वाणी पब्लिक डाटा ऑफिस (पीडीओ), पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर्स (पीडीओए) और वाई-फाई हॉटस्पॉट का वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान कर्नाटक में पीएम-वाणी योजना के अंतर्गत जिला-वार कितनी निश्धि आवंटित और उपयोग की गई है:

(ग) क्या सरकार ने कर्नाटक में विशेषकर कोलार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी, इंटरनेट की पहुंच, डिजिटल शिक्षा, ई-गवर्नेस और आजीविका के अवसरों पर पीएम-वाणी योजना के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पीएम-वाणी कवरेज का विस्तार करने, इंटरनेट की गुणवत्ता में सुधार करने, स्थानीय उद्यमियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और कर्नाटक के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों, विशेषकर कोलार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में वहनीय सार्वजनिक वाई-फाई सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) पिछले पाँच वर्षों में पीएम-वाणी के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में पंजीकृत सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) की वर्षवार एवं ज़िलावार संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

जिले का नाम	31.3.2022 तक कुल पीडीओ /वाई-फाई हॉटस्पॉट्स की संख्या	31.3.2023 तक कुल पीडीओ /वाई-फाई हॉटस्पॉट्स की संख्या	31.3.2024 तक कुल पीडीओ /वाई-फाई हॉटस्पॉट्स की संख्या	31.3.2025 तक कुल पीडीओ /वाई-फाई हॉटस्पॉट्स की संख्या	31.3.2026 तक कुल पीडीओ /वाई-फाई हॉटस्पॉट्स की संख्या
बागलकोट	270	422	422	422	424
बल्लारी	110	283	294	294	294
बेलागावी	548	907	908	908	908
बेंगलुरु ग्रामीण	1,061	1,155	1,158	1,164	1,166
बेंगलुरु शहरी	7,019	7,803	9,114	10,521	10,534
बीदर	12	216	241	241	241
चामराजनगर	145	195	195	197	197
चिक्काबल्लापुर	208	236	240	240	240
चिक्कमगलुरु	21	389	389	390	390
चित्रदुर्गा	366	500	500	500	500
दक्षिण कन्नड़	60	595	815	811	811
दावणगेरे	376	464	464	464	464
धारवाड़	342	590	590	590	590
गडग	117	235	235	235	235
हसन	261	529	529	529	529
हावेरी	61	190	190	190	190
कलबुर्गी	171	494	494	494	495
कोडागु	30	182	182	182	182
कोलार	60	320	323	330	330
कोप्पल	23	130	132	133	134
मांड्या	24	192	192	192	192
मैसूर	92	496	498	498	500
रायचूर	38	298	298	298	298
रामनगर	30	64	64	64	64
शिवमोग्गा	198	534	535	535	536
तुमकुरु	28	297	297	297	297

उडुपी	59	297	297	297	297
उत्तर कन्नड़	200	478	478	478	478
विजयपुरा	9	212	212	215	215
यादगीर	37	62	62	62	62
कुल	11,976	18,765	20,348	21,771	21,793

पिछले पाँच वर्षों में पीएम-वाणी के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में पंजीकृत सार्वजनिक डेटा कार्यालय एग्रीगेटर्स (पीडीओ) की वर्षवार एवं जिलावार संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

जिला	**31.3.2022 तक पीडीओ**	**31.3.2023 तक पीडीओ**	**31.3.2024 तक पीडीओ**	**31.3.2025 तक पीडीओ**	**31.3.2026 तक पीडीओ**
बागलकोट	0	0	0	0	0
बैंगलोर रूरल	0	0	0	0	0
बैंगलोर अर्बन	5	5	6	6	7
बेलगाम	1	1	1	1	1
बेल्लारी	0	0	0	0	0
बीदर	0	0	0	0	0
चामराजनगर	0	0	0	0	0
चिक्काबल्लापुर	0	0	0	0	0
चिक्कमगलुरु	0	0	0	0	0
चित्रदुर्गा	0	0	0	0	0
दक्षिण कन्नड़	0	0	0	0	0
दावणगेरे	0	0	0	0	0
धारवाड़	0	0	0	0	0
गडग	0	0	0	0	0
गुलबर्गा	0	0	0	0	0
हसन	0	0	0	0	0
हावेरी	0	0	0	0	0
कोडागु	0	0	0	0	0
कोलार	0	0	2	2	2
कोप्पल	0	1	1	1	1

मांड्या	0	0	0	0	0
मैसूर	0	1	1	1	1
रायचूर	0	0	0	0	0
रामनगर	0	0	0	0	0
शिमोगा	0	0	0	0	0
तुमकुर	0	0	0	0	0
उडुपी	0	0	0	0	0
उत्तर कन्नड़	1	1	1	1	1
विजयनगर	0	0	0	0	0
विजयपुरा	0	0	0	0	0
यादगीर	0	0	0	0	0
कुल	*7*	9	12	12	13

मौजूदा पीएम-वाणी संरचना के अंतर्गत, सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) और सार्वजनिक डेटा कार्यालय एग्रीगेटर्स (पीडीओ) की संख्या जिलावार दर्ज की जाती है। एक राज्य में पंजीकृत पीडीओ अन्य राज्यों में भी वाई-फाई हॉटस्पॉट सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं। पीएम-वाणी योजना के अंतर्गत पंजीकृत कुल यूनिक पीडीओ की संख्या 206 है।

(ख): पीएम-वाणी फ्रेमवर्क के अंतर्गत सेवाओं का प्रावधान पूर्णतः बाजार-आधारित है, जो किसी क्षेत्र में तकनीकी-वाणिजियिक व्यवहार्यता पर आधारित स्थानीय उद्यमशील पहल पर निर्भर करता है। सरकार की भूमिका केवल नीतिगत सुविधा प्रदान करने तक सीमित है, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों या किसी भी हितधारक को अलग से कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

(ग) एवं (घ): सरकार की भूमिका मुख्यतः नीतिगत सुविधा प्रदान करने की है। इसके अलावा, देशभर में, विशेषकर ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में पीएम-वाणी हॉटस्पॉट्स के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम-वाणी फ्रेमवर्क में निम्नलिखित नीतिगत हस्तक्षेप किए हैं:

(i) नियमित एफटीटीएच का उपयोग, एक ही बैकहॉल से अनेक एक्सेस पॉइंट्स का समेकन तथा द्वितीयक उपकरणों के लिए क्यूआर (क्यूआर) आधारित प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है, ताकि लागत कम की जा सके और सार्वजनिक डेटा कार्यालयों की व्यवहार्यता बढ़ाई जा सके।

(ii) मोबाइल डेटा ऑफलोडिंग तथा उपयोगकर्ताओं को प्रचारात्मक/ब्रांडिंग सामग्री भेजने की अनुमति दी गई है, ताकि व्यवहार्यता को और सुदृढ़ किया जा सके।

(iii) गृह एवं व्यावसायिक वाई-फाई को पीएम-वाणी से जोड़ने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, पीडीओ के बीच परस्पर रोमिंग को स्वीकृत किया गया है तथा सेवा सेट पहचानकर्ता (एसएसआईडी) के नाम का मानकीकरण किया गया है, ताकि आसानी से पता चल सके।

इसके अलावा, लागत कम करने और व्यवहार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) के लिए रिटेल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पर एक टैरिफ आदेश जारी किया है, कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को सभी रिटेल एफटीटीएच ब्रॉडबैंड योजनाएँ, पीडीओ को 200 मेगाबिट प्रति सेकंड तक अधिकतम स्पीड के साथ उस टैरिफ पर दें जो उपभोक्ता ब्रॉडबैंड टैरिफ से दोगुने से ज्यादा न हो।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने पीएम-वाणी फ्रेमवर्क के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाने और इसे अपनाने को प्रोत्साहित करने लिए व्यापक जागरूकता एवं पहुँच पहलें की हैं। दिनांक 30.06.2026 तक, डीओटी ने कर्नाटक राज्य में कुल 68 जागरूकता कार्यशालाएँ और 7 प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की हैं, साथ ही प्रिंट मीडिया में 3 विज्ञापन प्रकाशित किए हैं।

*****